

(25)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 8, 2011/पौष 18, 1932

No. 9]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 8, 2011/PAUSA 18, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2011

सं. 2/2011-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 10(अ).— केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) प्रस्तावना में, परंतुक में, खंड (झकझ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्

“(झकट) उक्त सारणी में क्रम सं० 37ग, 37घ, 37ड. के सामने विनिर्दिष्ट माल या 1 अप्रैल, 2011 के पश्चात्”

(ii) सारणी में, क्रम सं० 37ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“ 37ग.	1701	रॉ शुगर	कुछ नहीं	-	5घ
37घ.	1701 92 00 या 1701 99 90	रिफाईंड या सफेद शुगर	कुछ नहीं	-	5ड.
37ड.	1701	यदि रॉ शुगर थोक उपभोक्ता द्वारा आयातित है	कुछ नहीं	-	5च”

(iii) अनुबंध में, शर्त सं० 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जायेगी, अर्थात्

शर्त सं०	शर्त
“5घ	<p>(क) यदि शुगर फैक्ट्री या शुगर रिफाइनरी द्वारा आयात की गई हो ।</p> <p>स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए-</p> <p>(i) “शुगर फैक्ट्री” का वही अर्थ है जो धारा 2 (ग) शुगरकेन (कंट्रोल) आदेश 1966 के अंतर्गत है ।</p> <p>(ii) “शुगर रिफाइनरी” यानी वह यूनिट जो रॉ शुगरसे रिफाइंड शुगर बनाती हो ।</p> <p>(ख) यदि उपरोक्त (क) के अलावा कोई अन्य व्यक्ति आयात करता हो:</p> <p>(i) आयातकर्ता उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमा-शुल्क, के समक्ष शुगर फैक्ट्री या शुगर रिफाइनरी के साथ किया गया एग्रीमेंट या कंट्रैक्ट प्रस्तुत करेगा तथा एक बान्ड भी देगा यह करते हुए कि आयातित रॉ परिष्कृत करेगा;</p> <p>(ii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमा-शुल्क, आयातकर्ता को बान्ड से मुक्त कर देगा यदि आयातकर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा आयातित तारीख से तीन माह के भीतर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जो यह प्रमाणित करेकि सारी मात्रा की आयातित रॉ शुगर परिष्कृत कर दी गई है;</p> <p>(iii) यदि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन नहीं होता तो आयातकर्ता उस मात्रा की रॉ शुगर जो परिष्कृत नहीं की गई है पर लागू शुल्क अदा करेगा.”;</p>
5ड.	यदि आयातकर्ता उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमा-शुल्क के समक्ष यह प्रमाण प्रस्तुत करता है कि उसके पास जो आयात करने का कंट्रैक्ट वह एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलेपमेंट ऑथोरिटी (एपीडीए) के साथ रजिस्टर्ड है ।”
5च	<p>यदि आयातकर्ता, आयात के समय, थोक उपभोक्ता होने का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है ।</p> <p>स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-</p> <p>(i) थोक उपभोक्ता एक व्यक्ति, स्थापना या औद्योगिक इकाई है जो बिक्री के सिवाय उत्पादन या खपत या उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रति माह दस क्विंटल से अधिक का उपयोग करता हो ।</p> <p>(ii) उपरोक्त प्रमाण-पत्र किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ऐसे व्यक्ति, स्थापना या इकाई के पिछले बारह महीने में चीनी के मासिक उपयोग या खपत पर विचार करने के पश्चात् जारी किया जाएगा; और</p> <p>(iii) चार्टर्ड एकाउंटेंट का अर्थ वही होगा जो चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है ।</p>

[फा. सं. 354/78/2009-टी आर यू पार्ट I.]

विकास, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 128/2010-सीमाशुल्क, तारीख 22 दिसम्बर, 2010 सा०का०नि० 1002 (अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2011

No. 2/2011-CUSTOMS

G.S.R. 10(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 118(E) dated the 1st March, 2002, namely :-

In the said notification, -

(i) in the preamble, in the proviso, after clause (ia), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ia) the goods specified against S.Nos. 37C, 37D, 37E of the said Table on or after the 1st day of April, 2011”

(ii) in the Table, after S.No. 37B and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“37C.	1701	Raw Sugar	Nil	-	5D
37D.	1701 91 00 or 1701 99 90	Refined or white sugar	Nil	-	5E
37E.	1701	Raw sugar if imported by a bulk consumer	Nil	-	5F.”

(iii) in the Annexure, after condition No. 5 and the entries relating thereto, the following conditions shall be inserted, namely :-

Condition No.	Conditions
5D	(a) If imported by a sugar factory or a sugar refinery. Explanation.- For the purpose of this notification - (i) “sugar factory” shall have the same meaning as assigned to it in Section 2(c) of the Sugarcane (Control) Order, 1966;

	<p>(ii) “sugar refinery” means a unit which is engaged in the manufacture of refined sugar starting from the stage of raw sugar”.</p> <p>(b) If imported by any person other than at (a) above:</p> <ol style="list-style-type: none"> the importer shall produce to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a valid contract or agreement with a sugar factory or sugar refinery for refining of such raw sugar and shall furnish a bond to the effect that the said raw sugar shall be used for the said purpose; the bond shall be discharged by the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, on production of a certificate from the Central Excise authorities having jurisdiction over such sugar factory within a period of three months from the date of import of such raw sugar that the entire quantity of imported raw sugar has been refined and in the event of his failure to comply with the above conditions, the importer shall be liable to pay, in respect of such quantity of the raw sugar as is not proven to have been refined, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein.”;
5E	<p>If the importer produces before the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a proof to show that the contract for import of such sugar is duly registered with Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)”.</p>
5F	<p>If the importer, at the time of import, produces a certificate from a Chartered Accountant to the effect that the importer is a bulk consumer.</p> <p>Explanation,- For the purpose of this notification,-</p> <ol style="list-style-type: none"> bulk consumer is a person, establishment or industrial unit using or consuming more than ten quintals of sugar per month as a raw material for production or consumption or use in any manner other than sale. the said certificate shall be issued by the Chartered Accountant after taking into account monthly use or consumption of sugar by such person, establishment

	or unit in the last twelve months; and (iii) "Chartered Accountant" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Chartered Accountant Act, 1949.
--	---

[F.No.354/78/2009-TRU Pt. I]

VIKAS, Under Secy.

Note:— The principal notification No.21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 128/2010-Customs, dated the 22nd December, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.1002(E), dated the 22nd December, 2010.

59 58/11-2